आकाशवाणी केन्द्र शिमला

02.11.2025/प्रादेशिक समाचार/1800बजे

स्वास्थ्य सेवा

राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत अत्याधुनिक डायगनोस्टिक उपकरण स्थापित करने, बीमारियों का सटीक व समय पर पता लगाने और मरीज़ों के लिए जल्द उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए करीब 2 सौ 13 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिकीकरण के लिए योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीज़ों को महंगे इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज शिमला के रिज मैदान पर श्री गुरू तेग बहादुर जी के 3 सौ 50वें शहीदी दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री गुरू तेग बहादुर त्याग, तपस्या, भक्ति और मानवता की सेवा के मूल संदेश थे और सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस पावन अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोगों का इकट्ठा होना भारत की एकता और सौहार्द की भावना को दर्शाता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर सैनिक स्कूल को शिक्षा, खेल व सेना चयन में देशभर में सर्वश्रेष्ठ बताया है। सुजानपुर टिहरा सैनिक स्कूल के स्थापना दिवस और वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में एक हज़ार लोगों की क्षमता का इंडोर स्टेडियम विकसित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये स्टेडियम खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर सैनिक स्कूल के छात्र न केवल सेना बल्कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में भी अपने श्रेष्ठ कार्यशैली से देश का नाम रौशन कर रहे हैं।

जीएसटी

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितम्बर को शुरू हुए जी.एस.टी. बचत उत्सव से देशभर में लोगों को लाभ हो रहा है। इन सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है।

नए जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी उत्पादों पर टैक्स कम होने से परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। संशोधित कर ढांचे के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शॉर्पनर, इरेज़र और पेंसिल जैसी वस्तुओं को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार, पेंसिल बॉक्स और गणितीय उपकरण सहित शिक्षण सामग्री पर पहले के 12 प्रतिशत के बजाय कर की दरें अब केवल 5 प्रतिशत के बजाय कर की दरें अब केवल 5 प्रतिशत हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पुणे के एक अभिभावक, अतुल देशपांडे ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले की सराहना की है। मेरे दो बच्चे हैं छोटा लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बड़ी वो लड़की छठी कक्षा में पढ़ती है। नए जीएसटी दरों के वजह से जो स्कूल का खर्चा है, वह खर्चे में बचत होगी और जो कुछ

बचत होगी, वह हम अच्छी तरह से शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कटौती से परिवारों के लिए शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी आई है और घरेलू स्टेशनरी विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा ज़िले में शाहपुर क्षेत्र के डढम्भ में त्रैम्बला–ओला कूहल का शिलान्यास किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसल विविधिकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना के दूसरे चरण के तहत राज्य में एक हज़ार करोड़ रूपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। चंद्र कुमार ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से करने और किसान क्रैडिट कार्ड बनाने का आह्वान किया ताकि विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

दुर्घटना

शिमला ज़िला के नारकण्डा में बीती रात एक टैंपो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने से नेपाली मूल के 33 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को कुमारसैन के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गम्भीर रूप से घायल 16 लोग आई.जी.एम.सी. शिमला में उपचाराधीन है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज आई.जी.एम.सी. पहुंच कर घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने सभी घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

मंजूरी

राज्य सरकार ने भर्ती निदेशालय के तहत कनिष्ठ कार्यालय सहायक का अलग कैडर बनाने को स्वीकृति दी है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों के सुचारू संचालन के लिए पारदर्शिता और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रारंभिक रूप से राज्य कैडर में जॉब ट्रेनी के रूप में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 3 सौ पद सृजित किए गए हैं। ये पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर भरे जाएंगे।